भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 354
मंगलवार,15सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

354. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आगामी चार वर्षों के दौरान देश में केन्द्र अपनी 'मेक इन इंडिया' पहल हेतु भारी उद्योग क्षेत्र में और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग में इक्विटी को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए उदार और पारदर्शी नीति बनाई है जिसमें स्वचालित पद्धति के माध्यम से एफडीआई अधिकांश क्षेत्रों के लिए खुला है। भारत को निवेश के लिए अधिकाधिक आकर्षक और निवेशक-अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए सरकार समय-समय पर एफडीआई की नीतिगत प्रणाली की समीक्षा करती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, शीर्षस्थ उद्योग चैम्बरों, संघों और अन्य संगठनों सहित संबद्ध पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए भारी उद्योग क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में सुसंबद्ध तरीके से एफडीआई की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ): सरकार शेयर की आंशिक बिक्री और कार्यनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश की नीति अपनाती है। कार्यनीतिक विनिवेश में प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण सहित सीपीएसई की सरकारी शेयरधारिता की वास्तविक बिक्री शामिल होती है। कार्यनीतिक विनिवेश की नीति उन सीपीएसईज के संबंध में अपनाई जाती है जो "प्राथमिकता क्षेत्र" में नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए (i) राष्ट्रीय सुरक्षा (ii) संप्रभु कार्य की स्वतंत्रता (iii) बाजार की कमी और सार्वजनिक उद्देश्य के मानदंडों के आधार पर ऐसे सीपीएसईज की पहचान करने के लिए नीति आयोग को अधिदेशित किया गया है। कुछ अन्य सीपीएसईज में , एसईबीआई (सेबी) द्वारा अनुमोदित अनेक पद्धतियों के माध्यम से, प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किए बिना आंशिक हिस्सेदारी की बिक्री की नीति अपनाई जा रही है ताकि मूल्य का खुलासा हो सके , सार्वजनिक स्वामित्व को बढावा दिया जा सके और उच्चस्तरीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। शेयर की आंशिक बिक्री के लिए सामान्यतः प्रयुक्त विनिवेश पद्धतियों में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस), शेयरों की पुनः खरीद और विनिमय चालित निधियां (ईटीएफ) शामिल हैं। विनिवेश नीति में भारी उद्योग भी शामिल है।

विनिवेश एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है और कार्य सम्पादन का समय प्रचलित बाजार दशाओं और निवेशक की रूचि पर निर्भर करता है।

*****